

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- वेधना चौधरी, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:-160/2016/225 (2016/00160)

1. सुखदेव पुत्र स्व० बेणा (मृतक) जरिये वारिसान:-
    - 1/1- श्रीमती सोनी देवी पत्नि सुखदेव,
    - 1/2- सोहनसिंह पुत्र सुखदेव,
    - 1/3- पप्पी देवी पुत्री सुखदेव,
    - 1/4- सांवरसिंह पुत्र सुखदेव,
    - 1/5- शीला पुत्री सुखदेव
  2. उगमसिंह पुत्र स्व० बेणा,
  3. श्रीमती रतनी पत्नि स्व कालू,
  4. मदनसिंह पुत्र स्व० कालू,
  5. बीरम सिंह पुत्र स्व० कालू,
  6. श्रीमती नौरती पुत्री स्व० कालू
- समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बड़गांव, तह० व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम



2. गोपी पुत्र स्व० बीजा,  
मदन पुत्र स्व० बीजा (मृतक) जरिये वारिसान:-
  - 2/1- छोटी पत्नि मदन,
  - 2/2- दुर्गा पुत्र मदन,
  - 2/3- राजेन्द्र पुत्र मदन,
  - 2/4- लोकेश पुत्र मदन,
  - 2/5- पूजा पुत्री मदनसमस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह० व जिला अजमेर ।
3. सूरजमल पुत्र स्व० बीजा (मृतक) जरिये वारिसान:-
  - 3/1- प्रेम पुत्री सूरजमल,
  - 3/2- कूकड़ी पुत्री सूरजमल,
  - 3/3- मन्ना पुत्री सूरजमल,
  - 3/4- सांवर सिंह पुत्र सूरजमल.समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह० व जिला अजमेर ।
4. श्रीमती छोटी पुत्री स्व० बीजा पत्नि लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सवाईपुरा पोस्ट भगवानपुरा, तह० पुष्कर, जिला अजमेर ।
5. रामसिंह पुत्र दल्लासिंह (मृतक) जरिये वारिसान:-
  - 5/1- प्रभा पत्नि रामसिंह,
  - 5/2- महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह,
  - 5/3- शंकर पुत्र रामसिंह,
  - 5/4- प्रहलाद पुत्र रामसिंह,समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह० व जिला अजमेर ।
6. किशनसिंह पुत्र दल्लासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बालूपुरा रावतों का मौहल्ला, आदर्श नगर, अजमेर ।  
देवी सिंह पुत्र स्व० रामा, जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
8. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामा (मृतक) जरिये वारिसान:-
  - 8/1- श्रीमती गुमानी पत्नि लक्ष्मण,
  - 8/2- भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मण,
  - 8/3- महेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण,

W.S. -  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

- 8/4- तीजा पुत्री लक्ष्मण,  
 8/5- ज्ञानसिंह पुत्री लक्ष्मण,  
 8/6- नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मण,  
 समस्त जाति रावत, निवासी नया बड़गांव, तह0 माखुपुरा, जिला अजमेर।
9. तहसीलदार, अजमेर।  
 10. उप पंजीयक, अजमेर।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 30.7.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 71/2011.

उपस्थित:-

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांत संख्या 1/1 से 1/5.
2. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलान्त संख्या 2 से 6.
3. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पोंड संख्या 1 से 3/4.
4. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पोंड 4 से 6.
5. श्री एन0के0 जैन, वकील रेस्पोंड संख्या 7.
6. रेस्पोंड संख्या 8/1 से 8/6 अनुपस्थित !
7. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांक:- 14.1.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 30.7.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. वादीगण/अपीलांतस ने अधी0न्याया0 में वाद वास्ते उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोंड के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जवाना के वंशज व वारिसान है तथा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में जवाना की वंशावली अंकित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व काश्तकारी की आराजियात सारणी "अ" व "ब" ग्राम बड़गांव में अवस्थित है। जवाना की अविभाजित आराजियात में प्रार्थीगण के माता पिता का 1/2 हिस्सा है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 का 1/24, 1/24 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात जवाना की पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। सारणी "ब" में अंकित आराजी में स्व0 बेणा के नाम एक हिस्सा दर्ज है तथा बिरदा के वारिसान रामा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्से पर बीजा वल्द माला के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में स्व0 बेणा के वारिसान के नाम इंद्राज नहीं होकर गलती एवं सहवन की त्रुटि से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई है तथा उक्त अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये ही वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि ऐसा करने में अप्रार्थीगण कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने, हक, हिस्से की भूमि से वंचित हो जावेगें जिससे उनको अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अन्त में दिनांक 18.2.2011 को वाद कारण उत्पन्न होना पाया गया। तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने

*(Signature)*  
 राजस्थान अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर सारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए बहस बाबत एक शब्द भी अपने निर्णय में अंकित किये बिना दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये । अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा रहा है और रेस्पोंडेंटस को अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने की खुली छूट प्रदान करने जैसा आदेश दिनांक 30.7.2015 को पारित कर दिया । अधी०न्याया० के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलान्टस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात में अपीलान्टस एवं रेस्पोंडेंट का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है जिसका आज दिनांक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा ना ही पक्षकारान के मध्य कभी मौखिक बंटवारा हुआ है । आज भी वादग्रस्त भूमि पर शामिल रूप से काश्त करते आ रहे है लेकिन अब पक्षकारान संख्या में अधिक हो जाने से प्रत्येक समय लड़ाई झगड़े की आशंका उत्पन्न होती रहती है इस कारण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का न्यायिक बंटवारा किया जाना न्यायोचित है । ऐसी स्थिति में अधी०न्याया० को प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट के विरुद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिये थी लेकिन उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिये जो विधिविरुद्ध है । वादग्रस्त भूमि का न्यायिक बंटवारा नहीं होने से रेस्पोंडेंट के मन में बदनियति आ गई है जिससे रेस्पोंडेंट अपीलान्टस के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने पर हमेशा आमादा रहते है ऐसी स्थिति में अधी०न्याया० को प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । दौराने वाद व प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग खसरा संख्या 978/1063 रकबा 0.39 है० एवं खसरा संख्या 886/1167 रकबा 0.08 है० का बैचान दिनांक 17.12.2014 को कर दिया है जिसका उनको कोई हक, अधिकार नहीं था । इसके बावजूद अधी०न्याया० ने प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी०न्याया० ने बहस सुनने के बावजूद भी बहस बाबत एक शब्द भी अपने निर्णय में अंकित किये बिना प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान कर अधी०न्याया० ने एक प्रकार से रेस्पोंडेंट को अपीलान्टस के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं खुर्द बुर्द करने की खुली छूट प्रदान करने जैसा आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अप्रार्थीगण ने सारणी 'अ' में अंकित आराजियात बाबत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अधी०न्याया० ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर कोई प्रदान नहीं किये है तथा अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है । न्यायालय का कर्तव्य है कि दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित करे, लेकिन अधी०न्याया० द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की खुली छूट प्रदान कर दी है । यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि को बैचान अथवा खुर्दबुर्द करने से पाबंद नहीं किया गया तो वादग्रस्त आराजी को पुनः आगे बैचान करने में सफल हो जायेगें जिससे वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जो न्याय की सतई संशा



*(Signature)*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

नहीं है । अधी०न्याया० ने इस और ध्यान नहीं देकर आक्षेपित आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश दिनांक 30.7.2015 में यह संशोधन फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण/रेस्पो० को अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने एवं रहन, बेचान, मुंतकिल करने तथा जबरन अतिक्रमण कर भूमि की शक्ल परिवर्तित करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने रेस्पो० गोपी, सूरजमल व मदन के वारिसान द्वारा ग्राम बड़गांव के खसरा संख्या 886 के हिस्से के विक्रयपत्र की फोटो प्रति पेश की तथा अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2021 पार्ट-1 पेज 198, डी०एन०जे० 2014 पेज 35, ए०आई०आर० 1962 पेज 527, आर०आर०टी० 2021 पेज 1474 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है जो एक विधिक प्रक्रिया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि समस्त पक्षकारान की तामील उपरांत उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । अधी०न्याया० द्वारा दिनांक 30.7.2015 को कोई आदेश पारित नहीं किये है इसलिये अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।



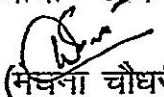
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी०न्याया० की आदेशिका दिनांक 30.7.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पत्रावली अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 व 9 की तलबी हेतु विचाराधीन थी । अधी०न्याया० ने अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 व 9 की तलबी हेतु आदेश दिये है जो एक विधिक प्रक्रिया है ना कि कोई अंतिम आदेश । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान की तलबी उपरांत साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । अधी०न्याया० की उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि अधी०न्याया० द्वारा किसी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण अधी०न्याया० के समक्ष 2011 से विचाराधीन है । हम न्यायहित में अधी०न्याया० को यह निर्देश देना उचित समझते है कि प्रकरण में शेष पक्षकारान की तलबी करवा कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को शीघ्रतिशीघ्र निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

  
(मेघना चौधरी)

राजस्थान अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.1.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

  
(मेघना चौधरी)

राजस्थान अपील प्राधिकारी,  
अजमेर